कोविड-19 और भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रयास

डॉ. बिन्दु श्रीवास्तव,
प्राध्यापक अर्थशास्त्र
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश -

कोविड-19 ने सारे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को विकास की पटरी से उतारकर ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जिसकी कल्पना शायद कभी किसी ने न की हो अचानक सभी देशों में लॉकडाउन होना किसी अप्रत्याशित घटना का ही पाठ हो सकता है भारत भी इससे अछूता नहीं रहा और भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की गति भी पटरी से उतर गई। जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याओं ने जन्म ले लिया। अतः इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने अथक प्रयास शुरू किये जिसमें 20 लाख करोड़ रुपये की घोषणा प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इस घोषणा में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के विकास का प्रावधान रखा गया ताकि सभी वर्गों के व्यक्तियों को सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इस समस्या के निदान के लिए निजी क्षेत्र का रुझान भी उल्लेखनीय है। अतः सरकार एवं निजी क्षेत्रों के प्रयासों से अर्थव्यवस्था को गति एवं आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने में सफलता का शंखनाद हो सकता है।

ुख्य शब्द - जनाभिमुखी योजना, आत्मनिर्भर, बेसिस।

अर्थव्यवस्था के पुनः आर्थिक विकास के अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए किये जा रहे प्रयत्नों के लिए ब हमें प्रयासरत् न होकर संघर्षरत् होना पड़ेगा क्योंकि आर्थिक विकास के प्रयास वर्तमान समय में किसी भी देश लिए सहज नहीं रह गए हैं विशेषतः विकासशील देश के लिए। विकास के प्रश्न विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न स्थानीय त्रीय, वर्गीय और सामाजिक विसंगतियों व विषमताओं की चुनौतियों से भरे होते हैं और अकादमिक व सैद्धांतिक नदण्डों पर आधारित किसी मार्ग पर चलते हुए भी वर्तमान समय में दुनिया के सभी राष्ट्र अभीष्ट मतंव्य की जगह क भिन्न अनापेक्षित एवं संकटपूर्ण आर्थिक ठिकाने पर जा पहुंचे हैं जहां से विकास के तमाम सुनहरे दिशा संकेत हसा अविश्वसनीय से प्रतीत हो रहे हैं। भारत भी इसी परिदृश्य में शामिल है क्योंकि कोवडि-19 महामारी ने सारे श्व की अर्थव्यवस्थाओं को विकास की पटरी से उतारकर ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जिसकी कल्पना ायद कभी कहीं भी न की हो अचानक सारे विश्व में लॉकडाउन होना किसी अप्रत्याशित घटना का सूचक हो सकता । भारत भी इससे अछूता नहीं रहा और यहाँ भी 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन घोषित हुआ जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की गति ही रुक गई चारों तरफ तरह-तरह की समस्याओं ने जन्म और सभी वर्गों (धनी, मध्यम, निर्धन) के क्तियों के जीवन यापन पर इसकी स्पष्ट छाप दिखाई देने लगी क्योंकि उद्योग, कारखाने, फेक्टरी से लेकर जमीनी वन जीने वाले खुदरा व्यापारी, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले, ठेले पर सामान रखकर जगह-जगह घूमकर सामान

बेचने वाले ही नहीं विभिन्न स्थानों पर काम करने वाला मजदूर वर्ग (सभी प्रकार के) यहां तक ही नहीं धार्मिक ... सड़क, रेल, वायु परिवहन सभी एक साथ बंद हो गए। जिससे सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई ... दुनिया में इस बीमारी के वायरस ने ऐसी रफ्तार पकड़ी की सरकारें समझ ही नहीं पाई कि क्या करें ऐसे ... लॉकडाउन ही व्यक्ति को सुरक्षित रखने का सहारा बना और मैं समझती हूं कि शायद भारत सरकार ने भी ... रहते सारे उपाय वो किए जिससे भारतीय सुरक्षित रह सके।

अब प्रश्न अर्थव्यवस्था के पुनः पटरी पर लाने का है? इसके लिए पुरजोर वे प्रयास करने होंगे जो ... हुई बेरोजगारी गरीबी, स्वास्थ्य, गिरती हुई जी.डी.पी. का प्रतिशत और अर्थव्यवस्था से जुड़े तीनों क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक सभी के लिए जनाभिमुखी योजनाओं का निर्माण करना होगा। इस संवंध में ग्रामीण बैंक के संस्थापक और नोवेल पुरुस्कार विजेता प्रख्यात अर्थशास्त्री मो. युनुस ने कहा है कि कोरोना संकट ने हमें नई दुनिया एवं वैकल्पिक अर्थव्यवस्था बनाने का मौका दिया है। अर्थव्यवस्था के देशी माडल को अपनाकर प्रवासी मजदूर एवं महिलाओं ... मदद से हम अर्थव्यवस्था को आगे ला सकते हैं। मजदूर शहरों में क्यों जाएं हम गांव में ही अर्थव्यवस्था क्यों ... खड़ी कर देते जब आज गांव में ही सभी तकनीक है तो मजदूर शहर न जाकर गांव में ही काम करें और अरबपति ... का धन एक ही दिशा में न बहे बल्कि उससे सभी लाभान्वित हों।[1]

यहां जवाहर लाल नेहरू जी का भी कथन समाचीन होगा उन्होंने कहा था - गांवों का रक्त शहरों के ... को मजबूत बनाने का सीमेंट बनाता है। मैं चाहता हूं यह रक्त जो शहरों की धमनियों को फुला रहा है पुनः ... की धमनियों में बहने लगे। यह कथन की सार्थकता आज के परिवेश में पूर्णतः लागू हो जाए तो हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना के विकास की रूकी गति को आगे वढ़ाने में सफलता की ओर वढ़ सकते हैं। चारों तरफ ... रही मांगे भी इसी ओर इंगित कर रही हैं कि पुराने महात्मा गांधी जी के ग्रामों के विकास के मॉडल को और ... निर्भरता को रामबाण बनाकर विकास यात्रा शुरू करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भी कल्पना आत्मनिर्भर ... को सफल बनाने में विकास के मार्ग को प्रशस्त कर सकेंगी। इसके लिए घरेलू व्यापार को बढ़ावा देना होगा, स्थानीय बाजारों के विस्तार पर ध्यान देना होगा। कृषि के विकास के साथ ही साथ आंतरिक व्यापार को बढ़ाने ... लिए संरक्षण की नीति द्वारा उद्योगों के विकास को भी बढ़ाना होगा। और पिछले सालों से चली आ रही आं... सुस्ती को भी आधार मानकर विकास की रणनीति तय की जाना चाहिए।

उपरोक्त वर्णित विकास के लिए भारतीय सरकार भी कटिबद्ध है इसको ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया गया जो विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए होगा इसे 5 किस्तों में ... जाएगा। 9 प्रमुख घोषणाओं में 3 प्रवासियों और दो किसानों से जुड़ी हैं। प्रवासी मजदूर के लिए 3500 करोड़ अनाज के लिए घोषित किए गए। बिना कार्ड के भी अनाज मिलेगा प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेंहू और प... को 1 किलो चना इससे 8 करोड़ प्रवासी लाभान्वित होंगे।[2] एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना भी लागू हो ज... जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर रोजगार पाने वालों को भी राशन कार्ड से अनाज मिल सकेगा। प... गरीब कल्याण अन्न योजना का भी विस्तार नवम्बर तक बढ़ाया गया है। 80 करोड़ लोगों को हर महिने एक ... चना मुफ्त मिलेगा जिसमें 90 लाख करोड़ का खर्चा आएगा।[3] तीसरी किस्त में एक लाख करोड़ रुपये का आधाभूत ढांचा बनेगा जिससे किसानों के उत्पीड़न को रोकने के लिए जोखिम रहित खेती एवं गुणवत्ता के मानकों

के लिए कानून बनाया जाएगा इतना ही नहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो कानून बनाया गया था उसमें सुधार से किसानों की आय बढ़ने की संभावना बढ़ेगी तिलहन, दलहन, आलू जैसे प्रोडेक्ट को रेग्यूलेट किया जाएगा किसानों को उचित मूल्य की व्यवस्था की जाएगी टाप टू टोटल योजना में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। यह पहले टमाटर, प्याज, आलू के लिए था आपरेशन ग्रीन का विस्तार कर इसे टमाटर, प्याज, आलू के अलावा सभी फल एवं सब्जियों के लिए किया जाएगा माल भाड़े में 50 फीसदी सब्सिडी होगी इसमें कोल्ड स्टोरेज शामिल होगा। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ की योजना है जो ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त आय का साधन होगा। हर्बल कल्टीवेशन के लिए 40 करोड़ का प्रावधान है। पशुपालन के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान है ताकि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर निर्यात के अवसर को बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10000 करोड़ रुपये की योजना है इससे रोजगार बढ़ेगा, मार्केटिंग ब्रांडिंग भी होगी और तकनीकी भी अपडेट होगी। इससे आने वाले समय में निर्यात बढ़ेगा एग्रीकल्चर कोआपरेटिव सोसायटी, कृषि स्टार्टअप आदि को लाभ होगा इस प्रकार सरकार और भी कई प्रयासों में लगी हुई है जिससे अर्थव्यवस्था के विकास की गति को बल मिले।

अब एक नजर में अर्थव्यवस्था के उन पहलुओं पर भी डालना जरूरी है (जैसे - मंहगाई की दर, जी.एस.टी., आर.बी.आई. के बेसिस पर, जी.डी.पी., भारत की रेटिंग एवं आयात व निर्यात) जिनके सुधार पर ही अर्थव्यवस्था के विकास के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। सबसे पहले मंहगाई दर-सब्जियों एवं अन्य खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से खुदरा मंहगाई दर जून में बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई है। सरकार के सोमवार के जारी आँकड़ों के अनुसार पिछले महिने खाद्य मुद्रा स्फीति बढ़कर 7.87 फीसदी हो गई पिछले जून महिने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मंहगाई दर 3.18 फीसदी थी।[5] और लाकडाउन में तो 1 फीसदी रह गई थी। और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की पूरी कोशिश रहती है कि मुद्रास्फीति 2 से 6 फीसदी के बीच रहे। (19 फरवरी 2020) अब अगर जी.एस.टी. की बात करें तो दिनांक 27.08.2020 फरवरी को वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण जी.एस.टी. कलेक्शन पर बहुत बुरा असर पड़ा है इसे दूर करने के लिए उन्होंने दो उपाय बताए - पहला केन्द्र सरकार से उधारी दूसरा आर.बी.आई. से उधारी करके उसे वित्त वर्ष में पूरा किया जाएगा। अब आर.बी.आई. के बेसिस की बात करें तो 20 लाख करोड़ रुपये की घोषणा होने के बाद आर.बी.आई. ने मार्च से अब तक 115 बेसिस पांइट्स की कमी कर चुका है परन्तु अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए और भी कदम उठाने की जरूरत है। जी.डी.पी. की स्थिति ने तो 40 साल का रिकार्ड तोड़ दिया है वित्त वर्ष 2020 की अप्रैल, जून तिमाही में भारत की जी.डी.पी. ग्रोथ में उम्मीद से ज्यादा गिरावट आई है यह ग्रोथ रेट - 23.9 फीसदी दर्ज की गई राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सकल मूल्य वर्धन 39.3 फीसदी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 50.3, बिजली में 7 फीसदी, उद्योग में जी.व्ही.ए. 38.1 फीसदी, सर्विस सेक्टर में 20.6 फीसदी, खनन क्षेत्र में जी.व्ही.ए. 23.3 फीसदी, ट्रेट एवं होटल में 47 फीसदी, एडमिनिस्ट्रेशन में 10.3 फीसदी और फाइनेंसियल स्टेट में 5.3 फीसदी रहा केवल एक मात्र कृषि क्षेत्र की ग्रोथ में 3.4 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।[6] अर्थात् सभी क्षेत्रों की ऋणात्मक गिरावट ने अर्थव्यवस्था को एक संकटपूर्ण स्थिति में ला दिया जिससे उबरने के लिए लगातार संघर्ष की आवश्यकता । रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग गिराकर 3003 पायदान पर पहुंचा दी है यह रेटिंग 22 सालों में सबसे

 ISSN 2321-631x

निचले स्तर पर पहुंच गई है जिसे निवेश ग्रेड का सबसे निचला पायदान कहा जा सकता है। तथा भारत को डाउनग्रेड किया है अन्य दो एजेन्सियां फिच और स्टैंडर्ड एण्ड पूअर पहले ही ये रेटिंग गिरा चुकी हैं ये डाउनग्रेड मूडीज के केवल कोरोना वायरस नहीं वरन अर्थव्यवस्था के खतरे पहले से ही पनप रहे थे और सरकारों का कर्ज 72 प्रतिशत था।[7] यदि आयात निर्यात की स्थिति पर नजर डालें तो चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल-जून के दौरान निर्यात 36.71 फीसदी घटकर 51.32 अरब डालर रहा जबकि आयात 52.43 फीसदी घटकर 60.44 अरब डालर रहा इसके वित्त वर्ष के पहले तीन महिने में व्यापार घाटा 9.12 अरब डालर रहा। हालांकि आयात में 47.59 फीसदी की गिरावट के कारण 18 सालों में पहली बार ट्रेड सरप्लस की स्थिति आई है क्योंकि तिलहन, काफी, चावल, तम्बाकू, मसाला, औषधि और रसायन के निर्यात में जून में वृद्धि दर्ज की गई।[8]

उपरोक्त विहंगम अर्थव्यवस्था के विश्लेषण से ये तो स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था को पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त करने में समय की नितांत आवश्यकता है क्योंकि विकास के चरण धीरे-धीरे ही आगे की ओर तब बढ़ पाते हैं जबकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र समान रूप से प्रगति के मार्ग पर चलें। इसके लिए सरकार के साथ-साथ आम जनता को भी समान रूप से अपनी सहभागिता निश्चित करनी होगी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मेरी समझ से निम्न सुझाव हो सकते हैं :-

(1) सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए जो भी योजनाएं, पैकेज, घोषणाएं की हैं उनका शत्-प्रतिशत लाभ उन लाभार्थी के पास पहुंच जाए जिनकी उन्हें जरूरत है उसके लिए तो एक निश्चित प्रको निर्मित करना होगा जिसमें ईमानदार व्यक्ति हो जो ईमानदारी के साथ काम भी करे और जो भ्रष्टाचा रिश्वतखोरी को पनपने ही न दे क्योंकि इसके चलते ही कोई योजना का पूरा का पूरा जन साधारण के पा पहुंचना संभव नहीं हो पाता है।

(2) जो गांवों से श्रमिक मजदूर वापिस नहीं लौट पा रहे हैं उनको रोजगार के लिए ग्रामों में पड़ी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर कृषि कार्य की ओर सुविधा देकर पहल की जा सकती है।

(3) सिंचाई के साधनों को वढ़ाने के लिए वेकार या पुर गये तालाबों व कुओं की खुदाई करवाकर उन्हें सिंचा योग्य बनाया जाए ताकि एक ओर रोजगार वढ़े दूसरी ओर सिंचाई के साधनों का विस्तार होगा।

(4) गांवों में पशुपालन को सरकार की योजना को फलीभूत करके वहाँ भी रोजगार की स्थिति को दुरुस्त कि जा सकता है।

(5) गांवों के जो लघु एवं कुटीर उद्योग मृतप्राय हो गए थे उन्हें संजीवनी बूटी से पुनः जीवित करके जो मज गांव पहुंच कर लौटना नहीं चाहते उन्हें रोजगार दिया जा सकता है।

(6) निजी क्षेत्र के सहयोग से घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को भी साकार किया सकता है, क्योंकि निजी क्षेत्र का रुझान भी इस ओर बढ़ रहा है।

उक्त सुझाव एक मत है। अर्थव्यवस्था के विकास की गति के लिए सभी क्षेत्रों के विकास के साथ कोविड-19 महामारी से सुरक्षा के लिए सरकार के साथ-साथ प्रत्येक भारतीय को भी सावधानी रखनी होगी ताकि भवि में व्यक्ति के साथ देश भी सुरक्षित रहे और अर्थव्यवस्था के विकास की गति भी पटरी पर आ सके।

सन्दर्भ -

(1) aajtak.in - नई दिल्ली, 31 जुलाई 2020

(2) समाचार पत्र - दैनिक भास्कर, जुलाई 2020

(3) दूरदर्शन समाचार - प्रधानमंत्री का सन्देश, 30 जून 2020, 4 बजे।

(4) बिजनेस डेस्क - 15 मई शुक्रवार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 3 किस्त की घोशणा के अंश लेखक - नीतेश।

(5) ZEE NEWS - 14 जुलाई 2020, 01:01 A.M. IST

(6) Financial Expreess - 01 सितम्बर, 2020, 03:12 PM.

(7) पत्रकार जोशी आलोक - लेख 2 जून, 2020

(8) Economics Time - 16 जुलाई, 2020, 03:37 PM.